बीएसएनएलईयू, एआईबीडीपीए और बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति

सीओसी/3/2021 **सर्कुलर** **02 नवंबर, 2021**

प्रिय साथियों,

बीएसएनएलईयू, एआईबीडीपीए, बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति की एक बैठक 26.10.2021 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। बैठक में बीएसएनएलईयू, एआईबीडीपीए, बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्ष कॉम. के. जी. जयराज ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में समन्वय समिति द्वारा शुरू किए गए आंदोलनकारी कार्यक्रम की समीक्षा की गई। एसएसए/बीए कार्यालय मार्च 05–10–2021 को और सीजीएम कार्यालय मार्च 22–10–2021 को कुल मिलाकर अच्छी भागीदारी के साथ आयोजित किये गये, जो समन्वय समिति के गठन और आयोजित किए जा रहे संघर्षों पर उत्साह को दर्शाता है। बैठक ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कुछ सर्किलों में कमजोरी को भी नोट किया और इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। बैठक में संविदा कर्मियों को बकाया वेतन भुगतान न होने और पेंशनभोगियों को चिकित्सा लाभ देने के ज्वलंत मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कॉमरेड पी अभिमन्यु, संयोजक, ने एयूएबी और बीएसएनएल के निदेशक मंडल के बीच 27–10–2021 को होने वाली बैठक में दोनों मुद्दों को उठाने पर सहमति व्यक्त की।

इसके अलावा, बैठक में **'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन'** के बारे में गहन चर्चा हुई। इसने गंभीर चिंता के साथ नोट किया कि सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के 14,917 मोबाइल टावर निजी हाथों में को सौंपने का फैसला किया है। बैठक में देखा गया कि, यह कुछ और नहीं बल्कि बीएसएनएल के निजीकरण की शुरुआत है।

बैठक में इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि इस साल के बजट में बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावरों और ऑप्टिक फाइबर का मुद्रीकरण करने और 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि, अगले कदम के रूप में, सरकार बीएसएनएल के ऑप्टिक फाइबर को भी कॉरपोरेट्स को सौंपने जा रही है। बीएसएनएल के मोबाइल टावर और ऑप्टिक फाइबर को सौंपना, बीएसएनएल को दूरसंचार क्षेत्र से खत्म करने के लिए सरकार की भयावह योजना का हिस्सा है।

बैठक में यह भी गंभीर चिंता का विषय था कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर, सरकार ने रेलगाड़ियों, रेलवे पटरियों, सड़कों, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ऑप्टिक फाइबर आदि जैसी मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति को भारतीय और विदेशी कॉरपोरेट्स को औने–पौने दाम पर सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार हास्यास्पद रूप से तर्क देती है कि, वह उपर्युक्त संपत्तियों को निजी संस्थाओं को पट्टे पर दे रही है और इन संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा।

हमें यह समझना चाहिए कि मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उतनी तेजी से निजीकरण करने में विफल रही है, जितनी तेजी से उसने योजना बनाई थी। यह भारतीय मजदूर वर्ग द्वारा आयोजित निजीकरण के खिलाफ निरंतर संघर्ष के कारण है। इसलिए, वह राष्ट्रीय संपत्ति को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लायी है।

समन्वय समिति का मानना है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम और आंदोलन आयोजित करना बीएसएनएल कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के साथ–साथ आकस्मिक और अनुबंध कर्मचारियों का कर्तव्य है। विस्तृत चर्चा के बाद समन्वय समिति ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के विरुद्ध निम्नलिखित अभियान/आंदोलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

(1) पर्चे 10.11.2021 तक अंग्रेजी और हिंदी में मुद्रित किए जाने हैं। पर्चों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना है और मुद्रित किया जाना है।
(2) राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ 09.11.2021 को सभी जगहों पर प्रदर्शन।
(3) कर्मचारियों और जनता के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाना।
(4) 30.11.2021 तक जिला एवं सर्किल स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं।

बैठक में सभी सर्किल और जिला समन्वय समितियों से उपरोक्त कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

(पी. अभिमन्यु)
संयोजक